प्रेषक,

जिला विद्यालय निरीक्षक
इलाहाबाद

सेवा में,

प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या
राजकीय / सवित्त / वित्तविहीन मान्यता प्राप्त
हाईस्कूल / इण्टरमीडिएट कालेज,
जनपद–इलाहाबाद

दिनांक- 23.1.2018

पत्रांक/ 17303 /2017

विषयः गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2018 के राष्ट्रीय पावन पर्व पर माननीय उप मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश एवं शिक्षा निदेशक(मा0)उत्तर प्रदेश का सन्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2018 के राष्ट्रीय पावन पर्व पर माननीय उप मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश एवं शिक्षा निदेशक(मा0)उत्तर प्रदेश का सन्देश संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः उक्तवत।

भवदीय

23.01.18

(आर0एन0विश्वकर्मा)
जिला विद्यालय निरीक्षक
इलाहाबाद

CJY 2016 I

(648)

16028
23-1-18

ई–मेल द्वारा

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक(मा0)
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

1–मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक,
उत्तर प्रदेश।

2–जिला विद्यालय निरीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक शिविर/24674-24814 /2017–18 दिनांक 22 जनवरी ,2018

विषयः–गणतन्त्र दिवस 26 जनवरी, 2018 के राष्ट्रीय पावन पर्व पर माननीय उप मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश एवं शिक्षा निदेशक (मा0) उत्तर प्रदेश का सन्देश।

महोदय,

गणतन्त्र दिवस 26 जनवरी, 2018 के राष्ट्रीय पावन पर्व पर माननीय उप मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश तथा शिक्षा निदेशक (मा0) उत्तर प्रदेश का सन्देश इस आशय से संलग्न कर प्रेषित है कि कृपया इसे अपने स्तर से मण्डल/जनपद के समस्त माध्यमिक कार्यालयों एवं विद्यालयों को समयान्तर्गत उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–उक्तवत।

भवदीय,

22/1/18

(भगवती सिंह)
उप शिक्षा निदेशक (शिविर)
कृते शिक्षा निदेशक(मा0)
उ0प्र0,लखनऊ

पृष्ठांकन संख्या–शिविर/24674-24814 /2017–18 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उक्त संदेश की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1–अपर शिक्षा निदेशक (मा0/व्या0शि0), उ0प्र0, इलाहाबाद/लखनऊ।
2–सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3–अपर सचिव, क्षेत्रीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा परिषद, मेरठ/वाराणसी/बरेली एवं इलाहाबाद
4–सचिव, माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
5–सहायक शिक्षा निदेशक (सेवा–1) प्रबन्ध अनुभाग, मुख्यालय, इलाहाबाद।
6–प्राचार्य, राज्य शिक्षा संस्थान, उ0प्र0, इलाहाबाद।

(भगवती सिंह)
उप शिक्षा निदेशक (शिविर)
कृते शिक्षा निदेशक(मा0)
उ0प्र0,लखनऊ

गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2018 के पावन राष्ट्रीय पर्व पर माननीय उप मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश का संदेश

15 अगस्त 1947 को स्वधीनता प्राप्ती के पश्चात 26 जनवरी 1950 को भारत को अपना संविधान लागू हुआ तथा एक सर्वजानिक गणतंत्र देश के रूप में युग का आरम्भ हुआ और आज हम सभी भारतवासी इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मना रहे हैं। यह अवसर हमें परतंत्र भारतीयों की दीन दशा, अंग्रेजी के अत्याचार, आजादी के लम्बे संघर्ष, जेल, गोली, फांसी एवं बलिदान के इतिहास को याद दिलाता है। इस दिन विश्व के सबसे बड़े संवैधानिक दस्तावेज भारतीय संविधान को लागू किया गया। अतः इस शुभअवसर पर हम संकल्प लेते हैं कि संविधान के नियमों का पालन करते हुए संकीर्ण भावनाओं से ऊपर उठकर भारतीय लोकतंत्र के निर्माण में सहायक होगें।

आजादी के बाद हम क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं। कुछ क्षेत्रों में तो विकसित देशों से भी आगे होने के दावा करने की स्थिति में हैं। ऐसा इसलिए संभव हुआ कि हमने स्वतंत्रता सेनानियों, देशभक्तों, महापुरूषों के त्याग एवं अमर शहीदों के बलिदान से प्रेरणा लेते हुए कठिन परिश्रम किया। हमारे महापुरूष हमारे लिए सदैव प्रेरणाश्रोत रहेगें। इम मातृभूमि के लिए गये उनके त्याग एवं बलिदान के प्रति अपनी कृतज्ञता एवं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।

किसी देश के विकास के लिए शिक्षा का विकसित होना अनिवार्य है। शिक्षा से जहॉ आदर्श समाज का निर्माण होता है वही रोजगार, अविषकार एवं सांस्कृति विचारों का प्रवाह उस देश में होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार नित प्रतिदिन कार्य कर रही है। हमने विगत वर्ष में सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनिकी एवं संस्कृति के क्षेत्र में आशातीत सफलता प्राप्त की है। जो हमारी गुणवत्ता एवं रोजगार परक संस्कृति शिक्षा निती का परिणाम है।

शिक्षा के क्षेत्र में माध्यमिक शिक्षा का अपना एक विशिष्ट स्थाना है। इसकी विशिष्टता एवं गुणवत्ता में वृद्धी के लिए निरंतर प्रयास जा रहे हैं। जिसके सुखद परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा को वर्तमान की अपेक्षाओं एवं मांग के अनुरूप बनाए जाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने

पुनरीक्षित पाठ्यक्रम लागू किया गया है तथा अनेक अभिनव प्रयास किये हैं, जिससे माध्यमिक शिक्षा को विशिष्ट बनाया जा सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु माध्यमिक शिक्षा में कई योजनायें संचालित की जा रही है।

कोई बालक/बालिका हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की गुणवत्तापरक शिक्षा से वंचित न रहे, इसके लिए पुनरीक्षित पाठ्यक्रम के अनुरूप पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था की गयी है जिससे लिंगभेद, सामाजिक एवं आर्थिक असमानता जैसी कुप्रवृत्तियाँ उत्पन्न न हों और माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता, सुदृढ़ता एवं समृद्धि का भी स्तर बना रहे।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 1486 नवीन राजकीय हाई स्कूल स्वीकृत हुए हैं, जिनमें से 1025 राजकीय हाई स्कूलों के भवन का निर्माण पूर्ण कराया जा चुका है।

छात्राओं के लिये राजकीय विद्यालयों विद्यालयों में स्वच्छ पेय जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु आर0ओ0 की व्यवस्था की गयी है। स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत विद्यालयों में पर्याप्त मात्रा में शौचालय बनवाये गये हैं।

केन्द्र पुरोनिधानित बालिका छात्रावास योजनान्तर्गत 191 बालिका छात्रावासों का निर्माण कराया जा रहा है। इन छात्रावासों में संबंधित विकास खण्ड के अपवंचित वर्ग की माध्यमिक स्तर की 100 छात्रायें प्रति छात्रावास में प्रवेश ले सकेंगी। माध्यमिक शिक्षा के ढांचे को सुदृढ़ एवं मजबूत आधार देने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा 166 पं0 दीनदयाल उपाध्याय माडल राजकीय इण्टर कालेजों के स्थापना का निर्णय लिया गया है, जिससे प्रदेश के असेवित क्षेत्र भी माध्यमिक विद्यालयों से आच्छादित हो सकें।

माध्यमिक शिक्षा में पहली बार 147 मेधावी छात्र–छात्राओं को रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार योजना के अन्तर्गत एक–एक लाख रूपये की धनराशि टेबलेट एवं प्रमाण पत्र देकर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पुरस्कृत किया गया है।

माध्यमिक स्तर पर 'समान राष्ट्रीय पाठ्यक्रम' को प्रदेश में लागू कर दिया गया है, जिससे गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान तथा जीव विज्ञान के पाठ्यक्रम को बदलकर राष्ट्रीय स्तर के पाठ्यक्रम के समतुल्य किया जा चुका है, जिससे सीखने, पढ़ने के साथ ही विद्यालयों एवं कक्षाओं का परिवेश सुव्यवस्थित हो सके।

प्रधानाचार्यों/शिक्षकों के दक्षता कौशल को बढ़ाने के लिए अभिनव प्रशिक्षण कार्यक्रम विभिन्न स्तर पर आयोजित हो रहे हैं, जिससे अध्यापकों और छात्रों को नवीन शैक्षिक तकनीकी का समुचित लाभ मिल सके। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस वर्ष से विद्यालयीय खेलकूद को बढ़ावा देने हेतु अनेक खेल प्रोत्साहन कार्यक्रम शुरू किये है।

प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक विद्यालय में बालिकाओं में आत्मरक्षा की भावना एवं दक्षता विकसित करने के उद्देश्य से रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कराया गया, जिसके माध्यम से लगभग 65 हजार छात्रायें प्रशिक्षित हो चुकी हैं।

प्रदेश के ऐसे युवक एवं युवतियों, जो माध्यमिक शिक्षा ग्रहण करने की इच्छुक हैं, परन्तु अपने दैनिक खर्च की पूर्ति हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यों यथा–खेती, मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों से जुड़े रहने के कारण माध्यमिक स्तर की शिक्षा पूर्ण नहीं कर पाते, उनके लिए पत्राचार शिक्षा के माध्यम से पत्राचार शिक्षा संस्थान द्वारा माध्यमिक शिक्षा प्रदान की जा रही है।

नवीन संस्थाओं/विद्यालयों को नवीन मान्यता प्रदान करने की प्रकिया को भी पूर्ण पारदर्शी बनाये जाने के दृष्टिगत मान्यता प्रदान करने की प्रकिया प्रथमबार ऑनलाइन करायी जा रही है।

माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षाओं के परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण में पूर्ण पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण प्रथमबार ऑनलाइन प्रविधि से कराया गया। इस वर्ष 2018 में गत वर्ष की तुलना में 6.5 लाख परीक्षार्थी बढ़ जाने के बावजूद, परीक्षा केन्द्रों की संख्या में 2866 कमी हुई है, जिससे नकलविहीन परीक्षा कराये जाने के निमित्त परीक्षा केन्द्रों का प्रभावी निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण किया जा सके। गत् वर्ष 11415 परीक्षा केन्द्र बनाये गये थे जबकि इस वर्ष विद्यालयों की धारण क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करते हुये 8549 परीक्षा केन्द्र बनाये गये हैं।

परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण हेतु विद्यालयों की स्थिति ज्ञात करने हेतु अर्थात उनके अक्षांश एवं देशान्तर तथा विद्यालयों के मध्य परस्पर सटीक दूरी ज्ञात करने हेतु प्रथम बार मोबाइल एप का प्रयोग किया गया, जिससे ऑनलाइन केन्द्र निर्धारण की प्रक्रिया सुगम एवं प्रभावी हो सकी।

नकल विहीन परीक्षा कराये जाने के दृष्टिगत इस वर्ष 2018 में निर्धारित किये गये समस्त परीक्षा केन्द्रों पर सी0सी0टी0वी0 लगाये जाने के निर्देश दिये गये हैं। इसके साथ ही साथ प्रयोगात्मक परीक्षाओं को भी सी0सी0टी0वी0 के समक्ष आयोजित कराये जाने एवं उनकी रिकार्डिंग को सुरक्षित रखने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

छात्र/छात्राओं के निमित्त शासन द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली विभिन्न योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने एवं छात्र/छात्राओं के फर्जी/बोगस पंजीकरण पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से शैक्षिक सत्र 2017–18 से प्रथम बार कक्षा–9 एवं 11 में पंजीकरण कराने वाले छात्र/छात्राओं के शैक्षिक विवरणों के साथ ही साथ उनकी आधार संख्या को भी आनलाइन अपलोड कराया गया है।

वैश्विक स्तर पर योग शिक्षा की बढ़ती महत्ता को देखते हुये तथा छात्र/छात्राओं के सर्वांगीण विकास के दृष्टिगत शैक्षिक सत्र 2017–18 से छात्र/छात्राओं के पाठ्यक्रम में योग शिक्षा को शामिल किया गया।

जनहित गारन्टी अधिनियम द्वारा आच्छादित माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा दी जा रही विभिन्न मैनुअल सेवाओं को प्रथम बार ऑनलाइन के माध्यम से प्रदान करने की कार्यवाही गतिमान है।

हमारा दृढ विश्वास है कि माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में उठाया गया हर कदम निश्चित रूप से विषमताओं को दूर करते हुए बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में सहायक होगा।

आज गणतंत्र दिवस के इस शुभ पावन अवसर पर मै प्रदेश के शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं अभिवावकों को हार्दिक बधाई देता हूँ, तथा अपेक्षा करता हूँ कि आप विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें जिससे कि उनके अन्तर्निहित क्षमता का संवर्द्धन हो सके तथा देश और प्रदेश अधिक सशक्त हो सके।

जय हिन्द जय भारत।

डा0 दिनेश शर्मा
उप मुख्यमंत्री
उत्तर प्रदेश।

गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2018 के अवसर पर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उत्तर प्रदेश का संदेश

गणतत्र दिवस प्रत्येक भारतवासी के लिए अत्यन्त गौरवशाली पावन पर्व है। यह राष्ट्रीय पर्व हमें उन स्वतंत्रता सेनानियों, देशभक्तों, महापुरूषों एवं अमर शहीदों की याद दिलाता है, जिन्होने अपने देश को स्वतन्त्र कराने के लिए सतत् संघर्ष करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिये। मातृभूमि पर प्राणोत्सर्ग करने वाले उन अमर शहीदों, राष्ट्रभक्तों के प्रति आज हम सभी श्रद्धा–सुमन अर्पित करते हैं।

सन 1947 में देश को आजादी मिलने के उपरान्त भाषा, क्षेत्र, प्रान्त तथा अन्य विविधताओं को एक सूत्र में पिरोकर सुशासन की स्थापना के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान की रचना की, जिसे हमने 26 जनवरी, 1950 को अंगीकृत किया, तत्पश्चात प्रदेश ने समस्त क्षेत्रों में उल्लेखनीय विकास किया।

भारतवर्ष विविधता का देश है, जहाँ भाषा, खान–पान, रीति–रिवाज क्षेत्र के अनुसार भिन्न–भिन्न हैं, किन्तु मूल्यों के सवाल पर सभी एक हैं। विविधता में एकता की यह मिसाल सम्भवतः सम्पूर्ण विश्व में कहीं और नहीं मिलती है। भारतवर्ष की आजादी के लिए सभी धर्म, सम्प्रदाय एवं जातियों ने मिलकर लड़ाई लड़ी है इसीलिए इस देश में एकता एवं अखण्डता की अक्षय धारा अक्षुण्ण रूप से प्रवाहमय है। एकता एवं अखण्डता की बलवती धारणा की आधारशिला पर खड़े होकर देश ने समस्त क्षेत्रों में आशातीत सफलता के साथ–साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की है।

माध्यमिक शिक्षा में पहली बार 147 मेधावियों को विगत वर्ष में रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार योजना के अन्तर्गत एक–एक लाख रूपये का चेक, टेबलेट एवं प्रमाण पत्र देकर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पुरस्कृत किया गया है।

शिक्षकों के दक्षता कौशल को बढ़ाने के लिए अभिनव प्रशिक्षण विभिन्न स्तरों पर आयोजित किये जा रहे हैं जिससे नित नवीन परिवर्तित हो रहे शैक्षिणिक कौशल से अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जा सके और छात्र–छात्राओं को इसका समुचित लाभ मिल सके।

प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक विद्यालय में बालिकाओं को आत्मासुरक्षा के दृष्टिकोण से रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण देते हुए अब तक राजकीय विद्यालयों की लगभग 6500 छात्राएं प्रशिक्षित की जा चुकी हैं।

छात्र–छात्राओं को रोजगारपरक शिक्षा देने हेतु अब तक प्रदान की जा रही व्यावसायिक शिक्षा को संवर्धित करते हुए चार नवीन ट्रेडों (रिटेल, आटोमोबाइल, स्क्यांरिटी एवम् सूचना प्रौद्योगिकी) को 200 राजकीय विद्यालयों में संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

प्रदेश में कोई भी छात्र/छात्रा माध्यमिक शिक्षा से वंचित न रह जाय इस हेतु उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रदेश में स्वीकृत 1486 नवीन हाईस्कूल के सापेक्ष 1025 राजकीय हाईस्कूलों के भवन का निर्माण पूर्ण कराया जा चुका है। बालिका छात्रावास योजनान्तर्गत 54 बालिका छात्रावासों का निर्माण कराया जा चुका है। इन छात्रावासों में सम्बन्धित विकास खण्ड के अपवंचित वर्ग के माध्यमिक स्तर की 191 छात्राएं प्रति छात्रावास प्रवेश ले सकेंगी।

प्रदेश के ऐसे छात्र–छात्राएँ जो माध्यमिक शिक्षा ग्रहण करने के इच्छुक तो हैं किन्तु जीविकोपार्जन हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यों यथा–खेती, मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों में व्यस्त रहने के कारण माध्यमिक स्तर की शिक्षा पूर्ण नही कर पाते, उन्हे पत्राचार शिक्षा संस्थान द्वारा पत्राचार शिक्षा के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा प्रदान की जा रही है।

माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षाओं के परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण में पूर्ण पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण प्रथमबार ऑनलाइन प्रविधि से कराया गया।

इस वर्ष 2018 में गत वर्ष की तुलना में 6.5 लाख परीक्षार्थी बढ़ जाने के बावजूद, परीक्षा केन्द्रों की संख्या में 2866 कमी हुई है, जिससे नकलविहीन परीक्षा कराये जाने के निमित्त परीक्षा केन्द्रों का प्रभावी निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण किया जा सके। गत् वर्ष 11415 परीक्षा केन्द्र बनाये गये थे जबकि इस वर्ष विद्यालयों की धारण क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करते हुये 8549 परीक्षा केन्द्र बनाये गये हैं।

नवीन संस्थाओं/विद्यालयों को नवीन मान्यता प्रदान करने की प्रकिया को भी पूर्ण पारदर्शी बनाये जाने के दृष्टिगत मान्यता प्रदान करने की प्रकिया प्रथमबार ऑनलाइन करायी जा रही है।

परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण हेतु विद्यालयों की स्थिति ज्ञात करने हेतु अर्थात उनके अक्षांश एवं देशान्तर तथा विद्यालयों के मध्य परस्पर सटीक दूरी ज्ञात करने हेतु प्रथम बार मोबाइल एप का प्रयोग किया गया, जिससे ऑनलाइन केन्द्र निर्धारण की प्रक्रिया सुगम एवं प्रभावी हो सकी।

नकल विहीन परीक्षा कराये जाने के दृष्टिगत इस वर्ष 2018 में निर्धारित किये गये समस्त परीक्षा केन्द्रों पर सी0सी0टी0वी0 लगाये जाने के निर्देश दिये गये हैं। इसके साथ ही साथ प्रयोगात्मक परीक्षाओं को भी सी0सी0टी0वी0 के समक्ष आयोजित कराये जाने एवं उनकी रिकार्डिंग को सुरक्षित रखने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

शैक्षिक सत्र 2018–19 से माध्यमिक शिक्षा की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में एन0सी0ई0आर0टी0 के पाठ्यक्रम को शामिल किया जा रहा है, जिससे माध्यमिक शिक्षा परिषद का पाठ्यक्रम लगभग सी0बी0एस0ई0 के समरूप हो सकें और राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 के परीक्षार्थियों का सफलता का स्तर और बढ़ सकें।

वैश्विक स्तर पर योग शिक्षा की बढ़ती महत्ता को देखते हुये तथा छात्र/छात्राओं के सर्वांगीण विकास के दृष्टिगत शैक्षिक सत्र 2017–18 से छात्र/छात्राओं के पाठ्यक्रम में योग शिक्षा को शामिल किया गया।

छात्र/छात्राओं के निमित्त शासन द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली विभिन्न योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने एवं छात्र/छात्राओं के फर्जी/बोगस पंजीकरण पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से शैक्षिक सत्र 2017–18 से प्रथम बार कक्षा–9 एवं 11 में पंजीकरण कराने वाले छात्र/छात्राओं के शैक्षिक विवरणों के साथ ही साथ उनकी आधार संख्या को भी आनलाइन अपलोड कराया गया है।

जनहित गारन्टी अधिनियम द्वारा आच्छादित माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा दी जा रही विभिन्न मैनुअल सेवाओं को प्रथम बार ऑनलाइन के माध्यम से प्रदान करने की कार्यवाही गतिमान है।

छात्र–छात्राओं के लिये विद्यालयों में स्वच्छ पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु आर0ओ0 की व्यवस्था की गयी है। स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत विद्यालयों में पर्याप्त मात्रा में शौचालय बनवाये गये है।

मैं, प्रदेश के सभी अधिकारियों, गुरूजनों, कर्मचारियों, एवं अभिवावकों को हार्दिक बधाई देते हुए यह अपेक्षा करता हूँ कि वे विद्यार्थियों को उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों का बोध कराये, जिससे वे अपनी शक्ति का उपयोग उचित दिशा में कर सकें तथा हमारा राष्ट्र और अधिक सशक्त हो सके।

अन्त में मैं, गणतन्त्र दिवस के इस पावन पर्व पर समस्त शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं अभिभावकों को हार्दिक बधाई देता हूँ साथ ही शुभकामना करता हूँ कि आप सभी गुणात्मक शिक्षा के संवर्द्धन में सहयोग कर सशक्त राष्ट्र का निर्माण करेंगे।

जय हिन्द, जय भारत।

डा0(अवध नरेश शर्मा)
शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)
उ0प्र0, लखनऊ।